भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 697

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

निधि का कम उपयोग

697. श्री राजा राम सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जल संसाधन विभाग ने दिसम्बर, 2024 के अंत तक वर्ष 2024-25 के अपने 21,640.88 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन में से केवल 58 प्रतिशत का ही उपयोग किया है और लगभग 40 प्रतिशत राशि खर्च नहीं हो पाई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निधि के संवितरण और परियोजना के निष्पादन में लगातार विलंब के क्या कारण हैं, विशेषकर तब जबकि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निधि स्वीकृत कर दी जाती हैं;

(ग) सरकार द्वारा सुदृढ़ बार्षिक निगरानी तंत्र स्थापित करने के बजाय मानसून के पश्चात तेजी का हवाला देते हुए कम उपयोग को लगातार न्यायोचित ठहराने के क्या कारण हैं;

(घ) 3,000 करोड़ रुपये के लंबित प्रस्तावों की स्थिति क्या है और इन्हें कब तक संस्वीकृत और जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का कार्यान्वयन निगरानी को सुदृढ़ करने, तकनीकी रिक्त पदों को भरने और महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को प्रशासनिक कमियों के कारण होने वाले विलंब से रोकने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का बजट अनुमान 21,323.10 करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके 21,640.88 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिसंबर 2024 तक बजट प्रावधानों के समक्ष विभाग का व्यय 12,655.52 करोड़ रुपए था, जो बजट अनुमान का 59.35% और विभाग के संशोधित अनुमान का 58.48% है। हालाँकि, संपूर्ण वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय 20,054.97 करोड़ रुपए रहा है, जो संशोधित अनुमान स्तर पर विभाग को आवंटित राशि का 92.6% है। निधि संवितरण में कोई विलंब नहीं हुआ है और न ही इसका उपयोग कम हुआ है।

(ङ): वित्तीय प्रबंधन और बढ़ावा देने के लिए, व्यय विभाग ने हाल ही में संशोधित प्रक्रिया लागू की है और केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एसएनए-एसपीएआरएसएच, सीएनए और टीएसए मॉड्यूल के माध्यम से समय पर निधि प्रवाह सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, परियोजना निगरानी समूह पोर्टल की शुरुआत ने परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं की निगरानी और समाधान को सुगम बनाकर कार्यान्वयन की निगरानी को और सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने रिक्त तकनीकी पदों सहित रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

*****